भारतीय राजनीति में धर्म-

भारतीय राजनीति में जाति की भांति धर्म भी अत्यधिक प्रभावशाली तत्व रहा है। राजनीतिक दल वोट बैंक के कारण धार्मिक जनभावनाओं को उभारा जाता है जिससे धर्म विशेष का समर्थन उन्हें हासिल हो सके। भारत में धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना के बाद भी धर्म एवं सम्प्रदाय भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है जिसके प्रभाव को निम्न रुपों में देखा जा सकता है-

1- धर्म एवं राजनीतिक दल- भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों के गठन एवं कार्यकरण की आधारशिला धर्म एवं साम्प्रदायिकता रही है। भारत में मुस्लिम लीग तथा हिन्दू महासभा अपनी प्रेरणा एवं समर्थन क्रमशः मुस्लिम धर्म तथा हिन्दू धर्म से प्राप्त करते हैं। शिरोमणि अकाली दल के निर्माण में भी सिखों की धार्मिक एवं साम्प्रदायिक भावनाएं महत्वपूर्ण हैं।

2- धर्म और निर्वाचन- स्वाधीनता के बाद चुनावों की राजनीति ने धर्म एवं सम्प्रदाय की राजनीतिक भूमिका को बढ़ाया है। भारत में चुनाव के समय प्रत्याशियों के चयन, राज्यस्तर के चुनाव तथा स्थानीय निकायों के चुनावों के समय देखने को मिलता है। वोट बटोरने के लिए मठाधीशों, इमामों तथा पादरियों के द्वारा अपने पक्ष में मत दिलवाए जाते हैं।

3- धर्म एवं मतदान व्यवहार- धर्म एवं साम्प्रदायिकता जैसे तथ्य भारतीय मतदाताओं में मतदान व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों, मुसलमान, सिख एवं ईसाइयों के साथ हमेशा ऐसी बात रही है। 6 दिसम्बर 1992 बाबरी ढांचा के पश्चात हुए चुनावों के दौरान साम्प्रदायिक मतदान व्यवहार देखने को आया।

4- धर्म एवं राजनीतिक पुरस्कारों का वितरण- आम निर्वाचन के पश्चात मंत्रिमण्डल के राजनीतिक पदों के वितरण धार्मिक एवं साम्प्रदायिक विचारों से प्रभावित होते हैं। केन्द्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री आवश्यक रुप से कुछ मुसलमानों सिखों तथा ईसाइयों को मंत्रिमण्डल में शामिल करता है। उसी प्रकार राज्य स्तर पर भी विभिन्न धार्मिक समुदाय को मंत्रिमण्डल में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसके

Scanned by TapScanner

अतिरिक्त व्यवस्थापिका एवं प्रशासन में भी पदों के बंटवारें में धार्मिक बातों का ध्यान रखा जाता है।

5- सरकारी नीति एवं कार्य तथा धर्म - सरकार की बहुत सारी नीतियाँ एवं कार्य भी धार्मिक एवं साम्प्रदायिक विचारों से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए भारत सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने में दिलचस्पी दिखाई है। बी. जे. पी., वी. एच. पी., शिवसेना आदि ने सरकार पर यह आरोप लगाया कि सरकार केवल हिन्दुओं की संख्या घटाने में ही दिलचस्पी रखती है। इस लिए मुसलमानों के संबंध में इस नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किया गया है।

Scanned by TapScanner

भारतीय राजनीति में जाति -

भारत में राजनीतिक व्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था एक दूसरे को प्रभावित करती है। सामाजिक व्यवस्था ~~के~~ ~~दूसरे को प्रभावित करती~~ है महत्वपूर्ण पहलुओं में जातिवाद एक महत्वपूर्ण पहलू है जो सम्पूर्ण राष्ट्र में राजनीति को प्रभावित करता है। रुडोल्फ ऐण्ड रुडोल्फ एवं हाईग्रेव जैसे विद्वानों का मत है कि भारतीय राजनीति तथा प्रशासन पर जाति का बहुत गहरा प्रभाव है। रुडोल्फ ने तो जाति को आधुनिकीकरण तथा संसदीय जनतंत्र की कार्यशीलता में सहायक बताया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर जाति का प्रभाव स्पष्ट रुप से राजनीतिक दलों, निर्वाचन की राजनीति, मतदान व्यवहार, राजनैतिक लाभों के वितरण तथा सरकारी निर्णयों आदि के संबंध में देखा जा सकता है।

1- जाति एवं राजनीतिक दल - भारत में मुख्य रुप से पिछले कुछ वर्षों में यह प्रवृत्ति देखने को मिली है कि राजनीतिक दलों का निर्माण जातिगत आधार पर होने लगता है। ऐसे राजनीतिक दल जातिवाद का नारा देकर ही अपने समर्थन का आधार बनाना चाहते हैं। डी.एम.के तथा ए.आई.डी.एम.के के निर्माण के पीछे ब्राह्मणवाद का विरोध ही मुख्य प्रेरक तत्व रहा है। पिछले कुछ वर्षों से बहुजन समाज पार्टी का आधार भी दलितों का समर्थक रहा है।

2- जातिवाद एवं निर्वाचन - पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम, विधान सभा एवं आम चुनाव के दौरान निर्वाचन के लिए राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चयन करते समय उनकी योग्यता से ज्यादा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न जातियों की जनसंख्या का विशेष रुप से ध्यान रखते हैं। चुनाव अभियान के समय भी राजनीतिक दलों द्वारा जातिवाद की भावना प्रायः उकसायी जाती है ताकि संबंधित प्रत्याशी को जाति के मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हो सके।

3- जातिवाद एवं मतदान व्यवहार - निर्वाचन में भारतीय मतदाताओं का व्यवहार भी निश्चित रुप से जातिवाद से प्रभावित रहा है। प्रत्याशी चाहे किसी भी दल का हो, उसकी जाति के लोगों का समर्थन उसे प्रायः मिलता रहता है। विशेष रुप से जाति ने मतदान व्यवहार को बिहार, उत्तर प्रदेश

Scanned by TapScanner

मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा हरियाणा में अधिक प्रभावित किया है।

4- जातिवाद एवं राजनीतिक पुरस्कारों का वितरण- राजनीतिक पदों एवं पुरस्कारों के वितरण में जाति के आधार पर भेदभाव का अस्तित्व कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जातिवाद का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित न रहकर प्रशासकीय क्षेत्र पर भी दिखाई पड़ता है। निगमों एवं आयोग की सदस्यता एवं अध्यक्षता में प्राय: जातीय प्रतिनिधित्व का ख्याल रखा जाता है। सरकारी पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के बीच धर्म तथा जाति के आधार पर भेदभाव किए जाने की घटनाएं सामने आती रही है।

5- जातिवाद एवं सरकारी निर्णय- भारत में जातिवाद ने सरकार के निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया को भी प्रभावित किया है। राज्यों के पुनर्गठन के समय केन्द्रीय सरकार ने इस बात का ध्यान रखा कि राज्यों का पुनर्गठन इस प्रकार किया जाय कि किसी एक जाति की अधिकांश संख्या राज्य में नहीं रहने पाए।

6- जातिवाद एवं राज्यों की राजनीति - यह बात सत्य है कि जाति राष्ट्रीय राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। परन्तु उससे भी अधिक प्रभाव राज्य स्तर की राजनीति में दिखाई देती है। भारत में विभिन्न राज्यों में राजनीति पर जातिवाद के प्रभाव चार प्रकार के रहे है। सर्वप्रथम तमिलनाडु में ब्राह्मण एवं निम्न जातियों में संघर्ष कायम है, जिसमें ब्राह्मण जाति पराजित हुआ महाराष्ट्र में राजनीतिक संघर्ष मराठा एवं ब्राह्मणों के बीच रही है। गुजरात, आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में कुछ मध्यम वर्गीय जातियां राजनीतिक संघर्ष में सक्रिय है।

कुल मिलाकर भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका नकारात्मक रही है।

Scanned by TapScanner